



UPVR010057642026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ द्रुतगामी न्यायालय प्रथम वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी-कुलदीप सिंह-II, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1898/2026

आलोक कुमार प्रजापति पुत्र रामनरेश प्रजापति निवासी मकान नं. 282 ए अकबरपुर सराय घाघ,
अकबरपुर मजार चौधरी, थाना सदर जिला कन्नौज।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उ०प्र०

.....अभियोजन पक्ष।

मु.अ.सं.-328/2026

अंतर्गत धारा-69,351(2) बी.एन.एस.

थाना-भेलूपुर, वाराणसी।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त आलोक कुमार प्रजापति पुत्र रामनरेश प्रजापति के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ आशीष कुमार का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।
2. वादिनी मुकदमा की तहरीर पर आवेदक/अभियुक्त आलोक कुमार प्रजापति के विरुद्ध मु.अ.सं. 328/2026 अंतर्गत धारा-69,351(2) बी.एन.एस.थाना-भेलूपुर में पंजीकृत किया गया है।
3. जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके पूर्व में मा० न्यायालय या मा० उच्च न्यायालय में न तो जमानत प्रार्थना निस्तारित है और न तो लंबित है। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप जैसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त को गलत एवं विधि विरुद्ध आधारों पर नामित कर चालान कर दिया गया है। अभियुक्त की जमानत अवर न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया गया है। अभियुक्त व वादिनी की शादी की बातचीत वर्ष 2024 में Shadi.Com के द्वारा शुरू हुआ था। किंतु वादी के पिता द्वारा शादी से इंकार कर दिया गया। तदोपरांत अभियुक्त की शादी दूसरी जगह तय हो गयी तब वादी द्वारा अनुचित दबाब बनाकर पैसे की मांग की गयी। अभियुक्त को वाराणसी पुलिस द्वारा फोन करके कन्नौज से वाराणसी दिनांक 03.06.2026 को बुलाया गया तथा अवैध धन की मांग की गयी। जब प्रार्थी द्वारा इंकार किया गया तो फर्जी कथानक के आधार पर एफ.आई.आर. लिखकर जेल भेज दिया गया। अतः जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।
4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान ए.डी.जी.सी. एवं वादी मुकदमा की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्रीमती उषा शुक्ला को विधिक सहायता हेतु नामित किया गया जिनकी ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।
5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त पर पीड़िता को शादी का झांसा देकर

जबरन शारीरिक संबंध बनाने व जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य आया है कि वादी मुकदमा/पीड़िता की मुलाकात आवेदक/अभियुक्त से Shadi.Com (Matrimonial website) पर वर्ष 2024 में हुयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा/पीड़िता ने आवेदक/अभियुक्त से बात चीत करने स्वीकार स्वीकार किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य है कि दिनांक 12.01.2025 को वाराणसी के अस्सी घाट स्थित होटल रूद्र गेस्ट हाउस में वादी मुकदमा/पीड़िता को अभियुक्त के परिवार द्वारा देखने व शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए बुलाया गया। जहां आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ उसका मुंह बंद करके जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया और आवेदक/अभियुक्त, वादी मुकदमा/पीड़िता के घर आया। वादी मुकदमा की मां, बहन से मिला शादी की बात शुरू की तथा तीन लाख रुपये दहेज की मांग की व मांग पूरी न होने पर शादी तोड़ने की धमकी दी। जब वादी मुकदमा/पीड़िता के मां बाप दहेज की रकम देने के तैयार हो गये तो इसके बाद भी आवेदक/अभियुक्त ने वादी मुकदमा/पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाये और बाद में आवेदक/अभियुक्त ने किसी अन्य लड़की से सगाई कर ली। वादी मुकदमा/पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है परंतु बयान अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में यह कथन किया है कि- आवेदक/अभियुक्त से Shadi.Com के जरिये दिसम्बर 2024 में मुलाकात हुयी। दिनांक 27.12.2024 को पहली बार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मिलने की बात कहकर पीड़िता को रूद्रा गेस्ट हाउस में दोपहर 12-01 के बीच बुलाया तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती कर संबंध बनाया गया। वापस आवेदक/अभियुक्त पीड़िता के कमरे पर आकर उस रात पीड़िता के साथ Physical हुआ। दिनांक 16.05.2026/17.05.2026 को अलका होटल में आवेदक/अभियुक्त तथा वादी मुकदमा/पीड़िता दो दिन तक साथ रहे और संबंध भी बने, जिसकी जानकारी दोनों के परिवार से सदस्यों को थी। वर्ष 2025 में कम से कम उभयपक्ष छः बार मिले और हर बार संबंध बना। वर्ष 2026 फरवरी और मार्च में भी होटल में संबंध बना। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट व पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में तार्किक विरोधाभास है। पीड़िता एक पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाली व्यस्क महिला है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित कृत्य की नैतिकता और उनके महत्व को समझने में भी सक्षम है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज लगभग डेढ़ वर्ष के विलंब से दर्ज करायी गयी है जिसका अभियोजन द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में दिनांक 03.06.2026 से निरुद्ध है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **महेश्वर टिगा बनाम झारखंड राज्य (2020)10 SCC 108 के पैरा 14** में प्रतिपादित किया है कि-

14. Under Section 90 IPC, a consent given under a misconception of fact is no consent in the eye of the law. But the misconception of fact has to be in proximity of time to the occurrence and cannot be spread over a period of four years. It hardly needs any elaboration that the consent by the appellant was a conscious and informed choice made by the after due deliberation, it being spread over a long period of time coupled with a conscious positive action not to protest. The prosecutrix in her letters to the appellant also mentions that there would often be quarrels at her home with her family members with regard to the relationship, and beatings given to her.

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **उदय बनाम स्टेट आफ कर्नाटक 2003 SCC (Cri) 775 के पैरा 21** में प्रतिपादित किया है कि-

21. It therefore appears that the consensus of judicial opinion is in favour

of the view that the consent given by the prosecutrix to sexual intercourse with a person with whom she is deeply in love on a promise that he would marry her on a later date, cannot be said to be given under a misconception of fact. A false promise is not a fact within the meaning of the Code. We are inclined to agree with this view, but we must add that there is no straitjacket formula for determining whether consent given by the prosecutrix to sexual intercourse is voluntary, or whether it is given under a misconception of fact. In the ultimate analysis, the tests laid down by the courts provide at best guidance to the judicial mind while considering a question of consent, but the court must, in each case consider the evidence before it and the surrounding circumstances, before reaching a conclusion, because each case has its own peculiar facts which may have a bearing on the question whether the consent was voluntary, or was given under a misconception of fact. It must also weigh the evidence keeping in view the fact that the burden is on the prosecution to prove each and every ingredient of the offence, absence of consent being one of them.

8. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व अभियुक्त की निरुद्धता अवधि व माननीय उच्चतम न्यायालय की विधिक नज़ीरों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

9. आवेदक/अभियुक्त आलोक कुमार प्रजापति की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1898/2026 मु.अ.सं.-328/2026 के मामले में मु० 1,00,000/-रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के एक जमानतदार दाखिल करने पर स्वीकृत किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त इस आशय का भी अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि-

- i. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई धमकी, वचन या लालच ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जो प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हो जिससे कि उसे न्यायालय के समक्ष या पुलिस अधिकारियों के समक्ष सही तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके।
- ii. आवेदक/अभियुक्त सक्षम न्यायालय को सूचित किये बिना भारत देश नहीं छोड़ेगा।

उपरोक्त जमानत आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक जिला कारागार वाराणसी को जरिये ई-मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये की आदेश का इंद्राज E-Prision Software में करें। यदि सात दिन के अंदर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव डी.एल.एस.ए. को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने की एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना संबंधित न्यायालय को अविलंब प्रेषित करें।

दिनांक-10.06.2026

बिकास कुमार
(आशुलिपिक)

(कुलदीप सिंह-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
द्वुतगामी प्रथम, वाराणसी।
जे.ओ कोड-यू.पी 1818